(c) what is the total amount likely to be spent on these schemes during the current financial year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON) : (a) Yes, Sir.

(b) Against the target of providing economic assistance to 9.21 lakh Scheduled Tribe families during the Seventh Plan, 6.81 lakh Scheduled Tribe families have been assisted during the first three years. No survey has been conducted in the State about the Scheduled Tribe families assisted to know the number who have crossed the poverty line.

(c) During the current year 1988-89, a total amount of Rs. 312.56 crores has been quantified by the State for Tribal Sub-Plan.

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी के निवासियों को नये राशनकार्ड जारी किया जाना

1202. श्री सुनील कुमार पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी के गरीब निवासियों को नए राशन कार्ड जारी किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और उसके परिणामस्वरूप उनको खाद्य वस्तुएं खुले बाजार में अधिक कीमत देकर खरीदनी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों को नये राशन कार्ड जारी करने का विचार रखती है और क्या कोई विसंगति सरकार के ध्यान में आयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने इसका खंडन किया है और कहा है कि पात्र व्यक्तियों को नए स्थायी राशन कार्ड जारी किए जाते है । दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए नीति-संबंधी निर्णय के अनुसार, झुग्गी/झोंपड़ियों तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके रहने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर अस्थायी कार्ड जारी किए जाते हैं । इस समय जैसाकि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को कोई अस्थायी कार्ड जारी नहीं किएजा रहे हैं ।

देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता

1203. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में खाद्यान्नों की राज्यवार आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस समय सरकार के विभिन्न सुरक्षित भण्डारों/भण्डार गृहों में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा उपलब्ध है ; और

(ग) निकट भविष्य में खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमे वर्ष 1987 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों के लिए की गई मांग का ब्यौरा दिया गया है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) पहली अप्रैल, 1988 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास कुल 94.3 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) देश के अन्दर वसूली अभियानों के जरिये तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब विदेशों से आयात कर स्टाक की नियमित रूप से भरपाई की जाती है ।